Concern over deaths of kids in road mishaps

At Children's Day nears, Consumers' Guild has urged the government to save those on the roads by passing the Motor Vehicles Amendment Bill-2017 in the forthcoming winter session of Parliament. In 2017, more than 9,000 children had died in road accidents in India comprising 6.4 per cent of all the road users who died in road casualties. The number of injuries to children in road mishaps are also increasing every year.

"Children are the future of our young nation and their safety and protection should be the country's top priority. Road crashes are impacting children directly, including their ability to attend school. One reason children are more severely impacted by road traffic crashes is their limited physical, cognitive and social behaviour which makes them more vulnerable road users than adults and susceptible to serious injury or death as a result of road crashes," said Abhishek Srivastava from the Consumers' Guild. India is a signatory to the Brasilia Declaration on Road Safety which aims to bring down road accidents by 50 per cent by 2020.

"This can only be achieved by having a stricter and stronger road safety law. The Motor Vehicles Amendment Bill, 2017, has already been cleared by the Lok Sabha in April 2017 and is due for passage by the Rajya Sabha.

"It is about time that we declare 'road safety a national priority' considering the fact that more than 400 people are dying on roads daily which is largely preventable," he said.

Consumer VOICE is leading a National Coalition of Road Safety which includes other organisations working on this issue. This National Coalition has been appealing to the Prime Minister and Union Minister of Road Transport and Highways for enhancing road safety for many months now. "If this Road Safety Bill is further deferred we will be putting at risk more precious lives before the next session of Parliament can adopt it. These casualties may include thousands of innocent children and youths in their productive years of life.

The passage of this bill is crucial in the forthcoming winter session," said Abhishek Srivastava.

The Consumers' Guild has been working on road safety since long and has submitted various representations to Central and state governments for bringing a strong law on road safety besides organising various educational activities. Some of the key provisions of the proposed bill include making safety belt or a child restraint system mandatory in a car for children below 14 years of age with a stiff penalty of Rs. 1,600. A guardian or owner shall be deemed to be guilty with Rs 25,000 penalty or 3 years' imprisonment with cancellation of registration of the vehicle for juvenile drivers and a penalty of Rs.1,800 and subsequent disqualification of driving licence for not wearing a helmet. Also, the annual publication, Road Accidents in India-2017, a report released by the Ministry of Road Transport and Highways, there were a total of 564,410 road accidents, 1.47,913, road traffic deaths and 4,69,972 injured persons in the year 2017.
मोटर वाहन संशोधन विध्यक पार्थिव हो

जासों, बंदीगढ़: कच्चे की सुखाई सुनिश्चित करने की दिशा में वाल विज्ञान के अवसर पर सरकार को प्रभावी कदम उठाना चाहिए। यह कहता है कि सबसे सुद्धा समाज के जीवन में भूमिका का। संगठन ने सरकार से चाहा है कि वह मोटर वाहन संशोधन विध्यक 2017 की राज्यव्यापी में पारित कर कड़े नियम लागू करे। लोग में यह पास हो जाने के बाद वह विध्यक राष्ट्र सभा में लिखा है। भारत में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं तमाम वचन अपनी जान बचाते है।

एनजीओ के अध्यक्ष सानीयाल ने बताया कि वचन नवाय देश के भविष्य हैं और उनकी सुखाई सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं में वचन की क्षति समाज और सरकार के लिए शर्मनाक बात है। भारत ने सड़क सुखाई पर ज्योतिर्लिंग धोखाधड़ी पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका लक्ष्य 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत की कमी करना है। और यह अभिलक्षित सड़क सुखता कानूनों के लागू होने पर ही किया जा सकता है। असीम ने बताया कि सड़क परिक्रमण और राज्यरूप मंत्रालय द्वारा जारी वाणिज्यिक रिपोर्ट ‘रोड एक्सीडेंट्स ‘हेनडिया’ 2017’ के अनुसार वर्ष 2017 में कुल 4,64,910 सड़क दुर्घटनाएँ हुईं जिसमें 1,47,913 मौतें हुईं और 4,70,975 घायल हुए।
बाल दिवस पर मोटर वाहन संशोधन विवेचन रैली करने का आह्वान

चंडीगढ़, 13 जनवरी (प्रायोजन) : बच्चों की सुरक्षा सुरक्षित करने की दिशा में बाल दिवस पर मोटर वाहन संशोधन विवेचन रैली करने का आह्वान किया गया है। इसके तहत मोटर वाहन संशोधन विवेचन रैली 2017 का आयोजन किया जा रहा है।

आज समाज नेटवर्क ने बच्चों को सुरक्षा सुरक्षित करने की दिशा में बाल दिवस पर मोटर वाहन संशोधन विवेचन रैली को सारांश देने वाला कवि प्रियंका ने इसकी आवश्यकता को राखीया।

इस रैली के लिए अभ्यासियों को निर्देश दिए गए हैं।
एक नज़र

वाहन संशोधन विधेयक पास करे राज्यसभा

चौथा चरण—वचनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बल दिखाने के अधिकार पर त्यागिय्य संगठन कंज़ोयर भौगोलिक ने सरकार से आरोप किया है कि वे मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2017 को राज्यसभा में पारित कर चौथे नियम लागू करें। लेकिन सामने में यह पास हो जाने के बाद यह विधेयक राज्य सभा में लगभग है। वर्ष 2017 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में पैदा होने वाले अधिक वचनों के लिए नीचे रहें लगा है। उन्नीसी शहरों में अन्तर्गत बच्चों के जाने वाले चौथे नियम लागू करें। लेकिन सामने में यह पास हो जाने के बाद यह विधेयक राज्य सभा में लगभग है। वर्ष 2017 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में जी हजार से भी अधिक वचनों के लिए नीचे रहें लगा है। उन्नीसी शहरों में अन्तर्गत बच्चों के जाने वाले चौथे नियम लागू करें।

Daily Pioneer

NGOS URGE GOVT TO SAVE CHILDREN ON ROADS ACCIDENT

Chandigarh: Committed towards the safety towards children, the Consumer Voice has urged the Government to save children on road accidents by passing the Motor Vehicle Amendment Bill-2017. “More than 9,000 children died in road casualties in India comprising 6.4 percent of all road users who died in road casualties. Unfortunately, these figures are increasing every year. If this road safety bill is further deferred, we will be putting at risk more precious lives before the next session of the Parliament can adopt it,” said Ashim Sanyal of Consumer Voice.

Dainik Jagran
मोटर वाहन संशोधन विधेयक पारित हो

दान चंद्रशंकर: कच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बाल दिवस के आयोजन पर सरकार की प्रभावी कदम उठाना बहाल है। यह कहना है कि स्वस्थ से समान स्वस्थ बालक-बालिका का।

संगठन ने सरकार से मांग की कि वे मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2017 को राज्यसभा में पारित करें। निम्नलिखित को पास हो जाने के बाद यह विधेयक जाता सभा में लिपित है।

सांसदों ने स्वस्थ्य विभाग का बताया कि कच्चे हमारे देश का भाषक है और उनकी सुरक्षा संरक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं में बच्चों की क्षति समाप्त और संरक्षण के लिए शर्मनाक बात है। भारत ने सड़क सुरक्षा पर आंदोलन की घोषणा पर हस्ताक्षर किया है, जिसका तत्काल 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50 पीसदी की कमी लाना है।

बाल दिवस पर मोटर वाहन संशोधन विधेयक पारित करने का आहार

चंद्रशंकर (राकेश): कच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बाल दिवस के अवसर पर स्वस्थ से समान स्वस्थ, कंजूमर व्यवस्था ने सरकार से आहार किया है कि वे मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2017 को राज्यसभा में पारित करें। निम्नलिखित को पास हो जाने के बाद यह विधेयक राज्य सभा में लिपित है।

2017 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 9 हजार से भी अधिक बच्चे जाने खेला चुके हैं। वह दुर्भाग्यवश उन अंकों में साल दर साल बढ़ती होती है। ए.जी. ओ. के अशोक सांताल ने बताया कि बच्चे हमारे देश का भाषक है और उनकी सुरक्षा संरक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं में बच्चों की क्षति समाप्त और संरक्षण के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। भारत ने सड़क सुरक्षा पर आंदोलन की घोषणा पर हस्ताक्षर किया है, जिसका तत्काल 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50 पीसदी की कमी लाना है।

सांसदों ने कहा कि सड़क परिक्रमण और राजमार्ग प्रशासन के जरूरी सामान रिपोर्ट एमडीएस इंडिया - 2017 के अनुसार वर्ष 2017 में कुल 4,64,910 सड़क दुर्घटनाओं हुई जिसमें 1,47,913 मौत हुई और 4,70,975 घायल हुए।
NGO urges govt to save children on road accidents

CHANDIGARH, NOV 13

Committed towards the safety towards Children day, Consumer Voice has urged the Govt to save children on road accidents by passing the motor vehicle amendment bill 2017. More than 9,000 children died in road casualties in India comprising 6.4% of all the road users who died in road casualties. Unfortunately, these figures are increasing every year. India is a signatory to the Brasilia Declaration on Road Safety which aims to bring down road accidents by 50% by 2020. This can only be achieved by having a stricter and stronger road safety law. The Motor Vehicles Amendment Bill 2017 has already been cleared by Lok Sabha in April, 2017 and is due for passage by the Rajya Sabha. “If this road safety bill is further deferred, we will be putting at risk more precious lives before the next session of the Parliament can adopt it. These casualties may include thousands of innocent children and youth in their productive years of life. The passage of Bill is crucial in the upcoming winter session” said Ashim Sanyal of Consumer Voice.

“As per the annual publication ‘Road Accidents in India-2017’ a report released by Ministry of Road Transport & Highways there were a total of 4,64,910 road accidents, 1,47,913, road traffic deaths and 4,70,975 persons injured in the year 2017” said Sanyal.
रिपोर्टः सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का सावधान, सड़क सुरक्षा नीति केंद्रीज
सड़क हादसों में मध्यप्रदेश में 962 बच्चों की मौत, देश का तीसरा राज्य बना हमारा प्रदेश

2017 में 53,177 लोगों के लिए एक सिलेंडर के रूप में नया सरायफ, जो 2016 में 56,467 हुई थी मौतें

31. दिनांक 27 जुलाई पर राजमार्ग मंत्री ने बताया कि उन्होंने अन्य क्षेत्रों में गाड़ियों का कीमती, जिसमें राजमार्ग, रेलवे और वायुयात्रा की सहायता प्राप्त की।

देश वाहन विभाग के प्रमुख ने वर्तमान में खुशी की आशा की।
MP records second-highest no. of kids’ deaths in road accidents

As per a ministry report, 962 children died in accidents in 2017

DH Post Correspondent

Bhopal: Madhya Pradesh recorded second highest number of deaths of children due to road accidents, according to the report Road Accidents in India 2017 issued by Union Ministry of Road Transport and Highways.

According to the report, in 2017, 962 children below 18 years of age died in road accidents in MP. The maximum in the country was in Uttar Pradesh at 2,231.

Also, among all the deaths in road accidents, the percentage of children’s death in MP is also second highest in the country at 9.8% (962 out of 9,877). In UP and Sikkim, children’s deaths made for 11.5% each of the total accidental deaths.

Citing these figures, the NGO National Centre for Human Settlements & Environment has urged the government for a quick passage of Motor Vehicles Amendment bill. The bill was passed by Lok Sabha in April 2017 but pending in Rajya Sabha. Retired DGP Arun Gauri said if the bill takes more time to be passed it will jeopardise many more young lives.
1 out of every 10 killed in road accident in MP is child: Report

Times News Network

Bhopal: Calling for measures to make roads safer for children, Bhopal-based National Centre for Human Settlements and Environment (NCHSE) has demanded that government makes safety belt or child restraint system mandatory in a car for children. Guardian/owner of vehicle should be held responsible for juveniles driving.

Ching a Union government report on Children’s Day, NCHSE, an NGO, has highlighted that third highest road accidents take place in MP. Last year, 57,532 road accidents occurred in the state resulting in 10,177 deaths and 53,399 injuries.

Last year, 57,532 road accidents occurred in the state resulting in 10,177 deaths and 53,399 injuries.

Every tenth person losing life in a road accident in the state is a child. Last year, 1,517 children died in road accidents in the state.

For every one lakh people, 18 die each year in road accidents. In India, one death occurs every 3.5 minutes due to road accidents. On this Children’s Day (November 14), the NCHSE urges government to save children on roads by passing the motor vehicles amendment bill 2017 in upcoming winter session of parliament.

“If this road safety bill is not passed, we will be putting at risk more precious live before next session of Parliament can adopt it. These casualties may include thousands of innocent children and youth in their respective years of life and the cost to the nation could be enormous. The passage of Bill is crucial in winter session,” said Arun Gunthoo, former IGP.

India is a signatory to the Brasilia Declaration on Road Safety which aims to bring down road accidents by 50% by 2020. This can only be achieved by having a strict and stringent road safety law, according to a press release by NCHSE.

The Assam Tribune

Plea to pass motor vehicle bill in Parliament winter session

Guwahati, Wednesday, November 14 2018

CPSU says 390 people die due to road accidents in Assam every year. An expert meeting to discuss an amendment bill of Motor Vehicles Act was held in New Delhi.

Dainik Purvodaya
Appeal Made to Pass Motor Vehicles Amendment Bill

By AKT Reuters, December 14, 2018

The Consumers’ Legal Protection Forum on Tuesday appealed the Central government to pass the Motor Vehicles Amendment Bill (MVA) in the ongoing session of Parliament.

"If this road safety bill is not passed, more precious lives will be at risk. The casualties may include thousands of innocent children and youth in their productive years of life. The passage of the bill in the upcoming winter session is crucial," said Ajay Sanyal, advocate and secretary, Consumers’ Legal Protection Forum.

In 2017, more than 20,000 children died in road casualties in India comprising 4.4 per cent of all who died in road accidents. The number of children getting injured in road mishaps is also increasing every year, the Forum stated.

Road crashes are impacting children directly, including those within the school. One reason why children are more severely impacted by road traffic crashes is their limited physical, cognitive and social behavior, which makes them more vulnerable to death and susceptible to serious injury or death as a result of road accidents.

"This is a call for the need for a National Road Safety Act to be brought down to road accidents by 50 per cent by 2020. This can only be achieved by having a stricter and stronger road safety law," the Forum said.

It is a high time road safety was accorded a national priority, considering the fact that more than 400 people are dying on roads daily, which are largely preventable, the Forum said.

Consumer VOICE is leading a National Coalition of Road Safety, which includes other organizations working on road safety such as Jaguar, CII, IIT Bombay, and Civil Action Group (CAG). The national coalition has been appealing to the Prime Minister and the Union Minister of Road Transport & Highways for enforcing road safety for many months now.

The bill proposes to make safety belts or child restraint system mandatory in cars for children below 14 years with the provision of a penalty of Rs 1,000. Moreover, the punishment for the owner shall be doubled with Rs 2,500 penalty and/or three years imprisonment with confiscation of registration of vehicle for juveniles below 14 years.

As per the annual publication Road Accidents in India-2017, a report released by the Ministry of Road Transport & Highways, there were a total of 480,950 road accidents, 1,47,193 road traffic deaths and 4,76,959 persons injured in the year 2017 alone.